RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 24 JULY TO 30 JULY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 44 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

क्विक डिलीवरी ने बदली लोगों की आदत 5 साल में दोगुनी हुई घर के जरूरी सामान की खरीदारी

Page 2

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $9.70 अरब बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर

Page 3

'कश्मीरी नीलम' की चमक दुनिया देखेगी, निर्यात बढ़ाने के लिए यह हुआ है काम

Page 5

editoria!

रोजगार बढ़ाने पर मुख्य ध्यान

आर्थिक सर्वेक्षण में प्रमुखता से रोजगार एवं कौशल की स्थिति पर विचार किया है. ये दोनों परस्पर संबंधित हैं. केंद्रीय बजट में भी रोजगार के मौके बढ़ाने को प्राथमिकता दी गयी है. इस संबंध में विभिन्न योजनाओं तथा प्रोत्साहन की घोषणा की गयी है. लेकिन अंतरिम बजट में जो इस संबंध में आवंटन प्रस्तावित था, वही आवंटन इस पूर्ण बजट में भी है. अलग से अतिरिक्त धन के लिए प्रावधान नहीं किया गया. लेकिन सरकार ने इन पहलों द्वारा एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि रोजगार बढ़ाना उसकी मुख्य प्राथमिकताओं में है. आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र को आगे आने की जरूरत है. बजट में जो प्रस्ताव हैं, उसमें भी यह दिखता है. निजी क्षेत्र रोजगार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में आगे आयेगा तथा सरकार रोजगार देने वाले और रोजगार पाने वाले को कुछ वित्तीय सहायता मुहैया करायेगी. आर्थिक सर्वेक्षण की यह बात सही है कि निजी क्षेत्र को अनेक प्रकार की कर राहतें दी गयी हैं तथा उनके मुनाफे में भारी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में यह उनका दायित्व बनता है कि वे रोजगार सृजन के लिए निवेश करें. बजट यह भी दिखाता है कि देश के श्रम बल का औपचारिककरण हो यानी अधिक से अधिक कामगारों को भविष्य निधि और अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए. कौशल विकास की चर्चा बजट में है, पर यह समय है कि स्किल इंडिया कार्यक्रम की अब तक उपलब्धियों और कमियों की ठीक से समीक्षा की जाए तथा उसके आधार पर आगे की योजना बने. देश की बड़ी कंपनियों द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण देने तथा सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं को वृत्ति देने की बात सराहनीय है. यदि यह ठीक से लागू होता है, तो श्रम बल की गुणवत्ता एवं क्षमता में बड़ी वृद्धि हो सकती है. कंपनियों को ऐसे कार्यक्रमों के लिए तैयार करना सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा. आयकर के संबंध में प्रावधान भले ही अपेक्षा के अनुरूप नहीं हों, पर नयी कर व्यवस्था में कटौती की सीमा बढ़ाना और स्लैबों की संख्या कम करना ठीक कदम है. पूंजीगत लाभ पर कर दरें बढ़ाने से कुछ तबकों में निराशा है, पर हमें यह सोचना चाहिए कि जिनके पास परिसंपत्तियां अधिक है और उनसे वे अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो उन्हें समुचित कर भी देना चाहिए. महत्वपूर्ण खनिजों और सौर ऊर्जा से संबंधित आधारभूत वस्तुओं पर आयात शुल्क हटाना या कम करना सराहनीय है, लेकिन सोने, चांदी, प्लेटिनम आदि के आयात शुल्क में कमी करना समझ से परे है. इससे आयात बढ़ेगा, जिसका सीधा असर चालू खाता घाटे के बढ़ने के रूप में होगा. स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर छूट से उत्पादन और उपभोग में वृद्धि होगी, जो अच्छी बात है.

सस्ती जमीन, किराए में मदद और विशेष पैकेज...

आईटी सेक्टर के लिए एमपी ने खोले नए राह

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

एमपी कैबिनेट ने निवेश को बढ़ाने के लिए आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश में आईटी नीति लागू हो गई है। इस नीति में आईटी सेक्टर के निवेशकों को लुभाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों को किराए मदद का प्रावधान नई पॉलिसी में की गई है। पहले इन कंपनियों को सस्ती जमीन इस शर्त पर दी जाती थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। अब यह बाध्यता खत्म हो गई है।

आईटी सेक्टर के निवेशकों को लुभाएगा मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में साल 2016 के बाद पहली बार नई आईटी नीति लागू हुई है। बदलते समय के साथ आईटी सेक्टर की जरूरतों को देखते हुए इस नई नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा बीपीओ कंपनियों को मिलेगा, जिन्हें अब सरकार किराए पर मदद करेगी।

इसमें किया गया है बदलाव

हालांकि नई आईटी नीति अक्टूबर 2023 में लागू हो गई थी। हाल ही में उसके दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मंगलवार को कैबिनेट ने इसमें संशोधन की मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही निवेशक नई नीति का लाभ उठा सकेंगे। इस पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद सरकार निवेशकों और क्वालिटी सर्टिफिकेशन में सरकार मदद करेगी। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में भी छूट दी जाएगी। इन छूटों से निवेशक आएंगे तो राज्य में आईटी सेक्टर में रोजगार बढ़ेंगे।

आईटी पार्क निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा

वहीं, नई नीति के तहत प्राइवेट डेवलपर्स को भी सर्व सुविधायुक्त आईटी पार्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डेवलपर्स खुद ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिससे निवेशकों को सीधे आकर काम शुरू करने की सुविधा मिलेगी। इससे परमिशन लेने में लगने वाला समय बचेगा और काम जल्दी शुरू हो सकेगा।

जमीन के बदले देनी होती थी नौकरी

पहले एक एकड़ जमीन लेने के लिए 100 नौकरियां देना जरूरी था। नई नीति में इस बाध्यता को हटा दिया गया है। अब कंपनियों को सीधे 75इ तक जमीन पर सब्सिडी मिलेगी। पहले जितनी नौकरियां कंपनी देने का वादा करती थी, उसी आधार पर उसे सस्ती जमीन मिलती थी। उदाहरण के लिए, एक एकड़ जमीन के लिए 100 नौकरियां देना जरूरी था। आईटी इनेबल्ड सर्विस यूनिट के लिए एक एकड़ में 150 नौकरियां और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक एकड़ में 50 नौकरियां देना अनिवार्य था। नई नीति से अब आईटी कंपनियां आसानी से जमीन ले सकेंगी।

पहले सिर्फ मिलती थी आर्थिक मदद

साल 2016 की नीति में सिर्फ स्थापना के लिए पूंजीगत सहायता मिलती थी। किराए की सहायता का कोई नियम नहीं था। डाटा सेंटर को भी पहले पूंजीगत खर्चों में सब्सिडी नहीं मिलती थी लेकिन नई नीति में इसे शामिल किया गया है।

ऑनलाइन होगी निवेश की प्रक्रिया

इसके साथ ही नई नीति में प्लग एंड प्ले आईटी पार्क बनाने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। पूरी निवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पहले अधिकतम 25 एकड़ तक जमीन दी जा सकती थी लेकिन अब उपलब्धता के आधार पर बड़ी जमीन भी आवंटित की जा सकेगी।

25 करोड़ तक की मिलेगी मदद

राज्य में बनने वाले पहले 5 आईटी पार्क को 25 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी। बाद में बनने वाले पार्क को 10 करोड़ रुपए और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग) के लिए कॉमन फैसिलिटीज पर 25 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी।

बड़े निवेशकों को अलग पैकेज

बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार विशेष पैकेज भी देगी। इसके तहत आईटी फर्म के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक, ईएसडीएम के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक और डाटा सेंटर में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने पर कंपनियों को अतिरिक्त सुविधाएं और छूट दी जाएंगी।

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, बुधवार (24 जुलाई) की शाम को 24 कैरेट सोना (Gold Rate) 69151 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 25 जुलाई की सुबह गिरावट के साथ 68177 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना-चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं।

सरकार ने बजट में सोने-चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती की है, जिसके बाद से लगातार सोने-चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है। बजट के अगले दिन भी भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। आज सोने की कीमत 68 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार देखी गई है। वहीं, चांदी का भाव 81 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक आ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत (Gold) 68177 रुपये है. जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी (Silver) का भाव 81801 रुपये किलो है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, बुधवार (24 जुलाई) की शाम को 24 कैरेट सोना 69151 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो , 25 जुलाई की सुबह गिरावट के साथ 68177 रुपये तक आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं।

बजाज फिनसर्व एएमसी ने केंद्रित रणनीति के साथ बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड लॉन्च किया

मुंबई। एजेंसी

बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के लॉन्च की घोषणा की है, जो इस श्रेणी में एक अनूठा फंड है, जिसमें उच्च सक्रिय शेयर और चुनिंदा 25-30 स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक केंद्रित रणनीति है। इस अनूठे दृष्टिकोण के माध्यम से, फंड का लक्ष्य लंबी अवधि में बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न प्रदान करना है। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि लार्ज कैप का वर्तमान मूल्यांकन उनके दीर्घकालिक औसत 23.1 (बारह महीने के मूल्य से आय अनुपात का दीर्घकालिक औसत) के करीब है। इससे पता चलता है कि लार्ज कैप वर्तमान में अपने उचित मूल्यांकन के करीब हैं, जिससे वे दीर्घकालिक निवेश के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बन गए हैं।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

भारत के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, जरा सी भी चूक बन जाती है हादसे का कारण, कई फ्लाइट हो चुकी हैं क्रैश

नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे के बाद टेबल टॉप एयरपोर्ट (ऊँत ऊदउ ग्ेिद्रू) फिर से सुर्खियों में हैं। इस विमान में 19 लोग सवार थे। इनमें से 18 की मौत हो चुकी है। टेबल टॉप एयरपोर्ट वे एयरपोर्ट होते हैं जो किसी पहाड़ पर मौजूद होते हैं। इनके रनवे पर एक तरफ या दोनों तरफ गहरी खाई होती है। जब भी कोई हवाई जहाज इन एयरपोर्ट पर उतरता है या टेक ऑफ करता है तो जरा सी चूक बड़े हादसे में बदल जाती है। दुनिया में कई देशों में टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं। भारत में भी 5 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो टेबल टॉप एयरपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं।

क्या होता है टेबल टॉप एयरपोर्ट?

इन एयरपोर्ट पर रनवे आम एयरपोर्ट के मुकाबले छोटा होता है। अगर पायलट सही समय पर फ्लाइट को टेक ऑफ या टच डाउन न करे तो प्लेन के खाई में गिरने की आशंका रहती है। वहीं कई बार फ्लाइट लैंड करते समय रनवे पर फिसल जाती है। इससे भी हवाई दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। इन एयरपोर्ट पर पायलट को काफी समझदारी दिखाने की जरूरत होती है।

शिमला एयरपोर्ट

हिमाचल प्रदेश के शिमला में बना यह एयरपोर्ट देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। इस एयरपोर्ट का रनवे मात्र 4035 फुट (1230 मीटर) लंबा है, जबकि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई इससे करीब 3 गुना ज्यादा है। दिल्ली एयरपोर्ट का यह रनवे 14,530 फुट लंबा है। शिमला के इस एयरपोर्ट से कई उड़ानें संचालित होती हैं।

कालीकट एयरपोर्ट

केरल का कालीकट एयरपोर्ट भी काफी खतरनाक है। इसे कोझिकोड एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एयरपोर्ट का रनवे 9383 फुट (2860 मीटर) लंबा है। इस एयरपोर्ट पर अगस्त 2020 में हादसा हो चुका है। दुबई से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट इस एयरपोर्ट पर लैंड होते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह फ्लाइट कोरोना के कारण दुबई में फंसे भारतीयों को लेकर आ रही थी। लैंडिंग के समय यह फ्लाइट रनवे से फिसल गई थी और करीब 30 फुट गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में दोनों पायलट और 19 यात्रियों की मौत हो गई थी।

मैंगलोर एयरपोर्ट

कर्नाटक में बना यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी प्लेन एक्सीडेंट का गवाह बन चुका है। टेबल टॉप पर बने इस एयरपोर्ट पर दो रनवे हैं। एक की लंबाई 5299 फुट (1615 मीटर) और दूसरे की लंबाई 8038 फुट (2450 मीटर) है। इस एयरपोर्ट पर वैसे तो कई हादसे हो चुके हैं लेकिन सबसे खतरनाक हादसा मई 2010 में हुआ था। एयर इंडिया की फ्लाइट दुबई से आ रही थी। यह फ्लाइट लैंड होने के बाद रनवे से आगे निकलकर एक खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 158 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी।

लेंगपुई एयरपोर्ट

यह एयरपोर्ट मिजोरम की राजधानी में बना है। इस एयरपोर्ट पर एक ही रनवे है जिसकी लंबाई 8200 फुट (2500 मीटर) है। इस एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी आदि के लिए उड़ान मिलती हैं। इस एयरपोर्ट पर भी कई हादसे हुए हैं। पहला हादसा मई 2011 में हुआ था। उस समय एक ट्रेनी हवाई जहाज इस एयरपोर्ट

के रनवे को पार कर खाई में गिर गया था। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। दूसरा हादसा इसी साल जनवरी में हुआ था। म्यांमार की सेना का एक प्लेन लैंडिंग के समय रनवे से फिसल गया था। इस हादसे में कुछ क्रू मेंबर घायल हो गए थे।

पेकंयांग एयरपोर्ट

सिक्किम का यह एयरपोर्ट भी टेबल टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल है। इस एयरपोर्ट का रनवे भी काफी छोटा है। इसकी लंबाई 5577 फुट (1700 मीटर) है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में किया था। खराब मौसम में यहां से उड़ानें अक्सर रद्द हो जाती हैं। इस एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट ज्यादा उड़ान भरती हैं। कई वजहों के चलते यहां से उड़ानें काफी समय के लिए बंद रही थीं। हाल ही में इस एयरपोर्ट से फिर से उड़ानें बहाल हुई हैं।

Google Map लाया सबसे जरूरी फीचर

अब फ्लाईओवर पर नहीं होगी कोई कंफ्यूजन

नई दिल्ली। एजेसी

गुगल मैप ने आखिरकार भारतीयों की मांग पूरी कर दी है, जिसका इंतजार हर भारतीय को लंबे वक्त से था। गूगल मैप की ओर से फ्लाईओवर कॉलआउट फीचर भारत में रोलआउट कर दिया है। इस फीचर को गूगल मैप के 40 शहरों में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे जल्द ही बाकी शहरों के यूजर्स को उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल इस फीचर को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही गध्ए यूजर्स के लिए इस फीचर को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

रास्तों और फ्लाईओवर का कंफ्यूजन होगा दूर

इसके अलावा गूगल की ओर से नैरो रोड फीचर को पेश किया गया है, जो चार पहिया वाहनों को पतले रास्तों में जाने से रोकने में मदद करेगा। दरअसल, अक्सर यूजर्स इस दुविधा में रहते हैं कि उन्हें सर्विस रोड लेनी चाहिए या फिर फ्लाईओवर लेना चाहिए, तो गूगल मैप ने इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है।

जल्द आएगा एंड्रॉइड ऑटो फीचर

गूगल की मानें, तो उनके पास फ्लाईओवर गाइडेंस को लेकर सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिल रही थीं। ऐसे में कंपनी ने फ्लाईओवर कॉलआउट फीचर को नेविगेशन के लिए इंटीग्रेट किया है, जो यूजर्स को अपकमिंग फ्लाईओवर और रूट की जानकारी देगा। यह फीचर एंड्रॉइड मैप और एंड्रॉइड ऑटो के लिए उपलब्ध होगा।

इन टेक्नोलॉजी का किया जाएगा यूज

गूगल की ओर से इंडियन रोड के लिए एक एआई मॉडल बनाया गया है, जो सड़क की चौड़ाई और लंबाई का अनुमान लगाता है। साथ ही रोड की इमेज के लिए सैटेलाइट का यूज किया जाएगा। इसमें सड़क टाइप, बिल्डिंग और रोड की जानकारी समय पर मिलेगी। गूगल लीडिंग इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग स्टेशन के साथ साझेदारी कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में गूगल मैप पर चार्जिंग स्टेशन की जानकारी दी जाएगी।

क्विक डिलीवरी ने बदली लोगों की आदत

5 साल में दोगुनी हुई घर के जरूरी सामान की खरीदारी

नई दिल्ली। एजेंसी

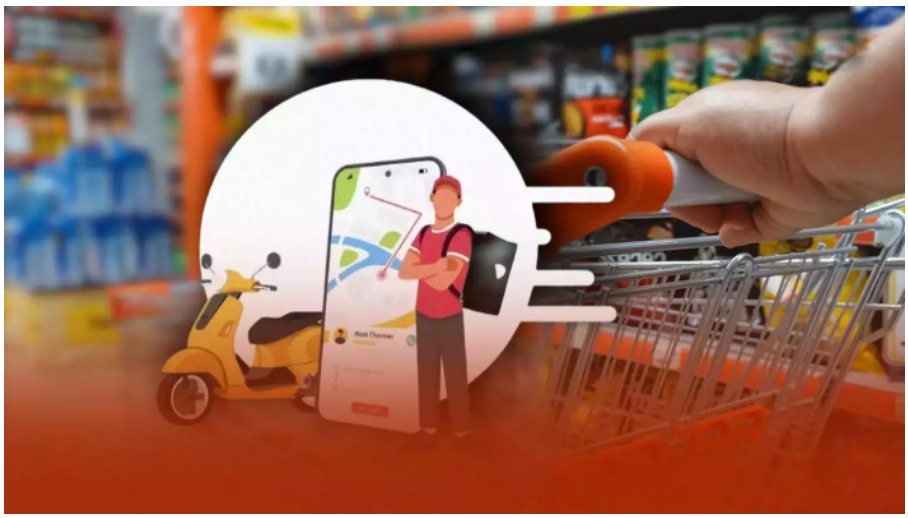

दिल्ली में रहने वाले रमेश (बदला हुआ नाम) पिछले कई महीने से घर का जरूरी सामान खरीदने रिटेल स्टोर नहीं गए हैं। उनकी पत्नी को अब यह नहीं पता कि उनकी सोसायटी के बाहर किराना की कोई नई दुकान खुली है या नहीं। यह सब इसलिए क्योंकि अब वह घर का सारा सामान ऑनलाइन ही मंगा लेती हैं। इस बारे में रमेश कहते हैं कि इससे न केवल समय बचाता है बल्कि कई चीजें सस्ती भी मिल जाती हैं। ऐसा सिर्फ रमेश और उनकी पत्नी ही नहीं कर रहे, इस समय ज्यादातर लोग घर के सामान की खरीदारी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कम समय में ही घर बैठे सामान आ जाता है।

खबर के मुताबिक क्विक डिलीवरी (ैंल्म्० अत्नेब) ने लोगों की खरीदारी की आदत को बदल दिया है। साथ ही लोग अब पहले के मुकाबले रोजाना की जरूरत की चीजों को जल्दी-जल्दी और ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं। खरीदारी के इस बदलाव के कारण रिटेल स्टोर के विक्रेताओं को भी ऑर्डर डिलीवरी करने के तरीके में बदलाव करने पड़ रहे हैं। एक्सपर्ट और इश्ण्उ कंपनी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि क्विक ई-कॉमर्स की वजह से ग्राहकों को जरूरत का सामान अब घर बैठे तुरंत मिल जाता है। Blinkit और Zepto जैसे प्लेटफॉर्म ग्राहक को सामान 10 मिनट में पहुंचाने का दावा करते हैं।

हर 56 घंटे में एक बार खरीदारी

लोगों की खरीदारी की लेकर रिसर्च फर्म कैंटार (Kantar) ने इस महीने डेटा जारी किया है। इस डेटा के अनुसार भारतीय इश्ण्उ उत्पादों के लिए एक साल में 156 बार खरीदारी कर रहे हैं। यानी हर 56 घंटे में एक बार। FMCG इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यह संख्या 5 साल में करीब दोगुनी है। 5 साल पहले भारतीय एक साल में 80 से 90 बार खरीदारी करते थे। कैंटार ने कहा कि पिछली चार तिमाहियों में एक तिमाही में खरीदे गए इश्ण्उ पैक की संख्या 199 से 202 के बीच रही।

खुदरा विक्रेता भी ऑनलाइन डिलीवरी को दे रहे बढ़ावा

ऑनलाइन डिलीवरी का असर खुदरा विक्रेताओं यानी रिटेल स्टोर पर भी दिखाई दे रहा है। ग्राहक तक पहुंच बनाने के लिए ये भी ऑनलाइन डिलीवरी का सहारा ले रहे है। इनमें रिलायंस रिटेल और स्पेंसर रिटेल जैसे स्टोर शामिल हैं। ये खुदरा विक्रेता ऑनलाइन ऑर्डर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपने डिलीवरी समय को कम कर रहे हैं। वहीं ई-कॉमर्स फर्म अमेजन तेजी से ऑर्डर पूरा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की

क्विक कॉमर्स सेवा शुरू की है।कम हो रही मासिक खरीदारी

बिस्कुट और स्नैक बनाने वाली कंपनी पारले प्रोडक्ट्स के सीनियर कैटेगरी हेड (मार्केटिंग) कृष्णराव बुद्ध ने कहा, 'हर साल मासिक किराना शॉपिंग बास्केट का आकार घट रहा है, क्योंकि उपभोक्ता क्विक कॉमर्स और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा के कारण जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं और रिटेलर डिलीवरी का समय कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल इश्ण्उ के लिए शॉपिंग ट्रिप या ऑर्डर की संख्या में 15-20% की बढ़ोतरी हो रही है।

GST स्लैब में बड़े बदलाव की तैयारी, सरकार की ओर से बताया गया पूरा प्लान

केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर तीन पर लाने की योजना बना रही है। इस बदलाव के संबंध में सरकार के एक अधिकारी ने संकेत दिए हैं।

GST Slab: आने वाले दिनों में जीएसटी

(गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) स्लैब में बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब में बदलाव करने की योजना बना रही है। इस बदलाव के संबंध में सरकार के एक अधिकारी ने संकेत दिए हैं। बता दें कि साल 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। इसके तहत लगभग 17 स्थानीय कर एवं उपकर शामिल किए गए।

अधिकारी ने क्या कहा?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बुधवार को एक इंटरव्यू में कहा- जीएसटी में बहुत अधिक स्लैब रेट वर्गीकरण विवादों को जन्म दे रही हैं और इसके समाधान की जरूरत है। अग्रवाल ने कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद से टैक्स स्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। इससे सरकार को स्लैब की समीक्षा करने की गुंजाइश मिलती है।

अग्रवाल ने कहा कि सरकार का इरादा 5%, 12%, 18% और 28% के मौजूदा स्लैब को 2 स्लैब में बदलना है। इसके जरिए जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाया जा सकता है। नई दरें रेवेन्यू कलेक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी। इसकी कवायद अगले कुछ महीनों में शुरू की जाएगी।

अधिकारी ने क्या कहा?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बुधवार को एक इंटरव्यू में कहा- जीएसटी में बहुत अधिक स्लैब रेट वर्गीकरण विवादों को जन्म दे रही हैं और इसके समाधान की जरूरत है। अग्रवाल ने कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद से टैक्स स्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। इससे सरकार को स्लैब की समीक्षा करने की गुंजाइश मिलती है।

अग्रवाल ने कहा कि सरकार का इरादा 5%, 12%, 18% और 28% के मौजूदा स्लैब को 2 स्लैब में बदलना है। इसके जरिए जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाया जा सकता है। नई दरें रेवेन्यू कलेक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी। इसकी कवायद अगले कुछ महीनों में शुरू की जाएगी।

बजट में कैंसर की दवाओं पर छूट से केवल एक कंपनी को होगा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

हाल में पेश बजट में कैंसर की तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की थी। लेकिन इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इससे केवल एक मल्टीनेशनल कंपनी एस्ट्राजेनेका को ही फायदा होगा। उनका कहना है कि यह छूट कैंसर दवाओं की पूरी कैटगरी या क्लास पर लागू नहीं होती है और इससे प्रत्येक शीशी/स्ट्रिप पर औसतन 18,000 रुपये का मामूली फायदा होगा। पिछले दो दिनों में एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया के शेयरों में बीएसई पर 13% से अधिक तेजी आई है। हालांकि आज शुरुआती कारोबार में इसमें एक फीसदी से अधिक गिरावट देखी जा रही है। फार्मा इंडस्ट्री, पेशंट ग्रुप और बायोकॉन जैसी घरेलू फार्मा कंपनियों ने कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर जीएसटी हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि इससे मरीजों और हेल्थकेयर सिस्टम को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता मिलेगी। एक एमएनसी कंपनी के अधिकारी ने कहा कि कस्टम ड्यूटी में छूट सभी कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की सभी इंपोर्टेड दवाओं पर लागू की जानी चाहिए। इसे केवल एक कैटगरी तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। बजट में कैंसर की तीन दवाओं Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib और Durvalumab को 10% सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। Trastuzumab Deruxtecan स्तन कैंसर की दवा है, ओसिमर्टिनिब फेफड़ों के कैंसर की दवा है और Durvalumab फेफड़ों और पित्त नली के कैंसर के इलाज में काम आती है।

दोहरी मार:- बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि तीन कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने से कैंसर रोगियों को राहत मिलेगी। हालांकि, सरकार को कैंसर के इलाज को रोगियों के लिए अधिक किफायती बनाने के लिए सभी कैंसर दवाओं के लिए जीएसटी छूट पर विचार करना चाहिए। अभी मरीजों को 10% के सीमा शुल्क और 12% के जीएसटी के साथ दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इससे आयातित दवाओं की कीमत में काफी बढ़ोतरी हो रही है। फिक्की के एक प्रतिनिधि ने कहा कि हम कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की सभी दवाओं पर सीमा शुल्क माफ करने और दवाओं पर जीएसटी में कमी का सरकार से फिर से अनुरोध करेंगे।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $9.70 अरब बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर

नई दिल्ली। एजेंसी

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 9.70 अरब डॉलर उछल कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 666.85 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह में कुल मुद्रा भंडार 5.16 अरब डॉलर बढ़कर 657.15 अरब डॉलर हो गया था। यह इससे पहले के उच्चतम स्तर 655.82 अरब डॉलर को पार कर गया। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा हुआ है। यह 1.90 करोड़ डॉलर बढ़कर 9.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया।रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 8.36 अरब डॉलर बढ़कर 585.47 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है।

गोल्ड रिजर्व में 1.23 अरब डॉलर की बढ़त

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार यानी गोल्ड रिजर्व का मूल्य 1.23 अरब डॉलर बढ़कर 58.66 अरब डॉलर रहा।

आईएमएफ के पास आरक्षित जमा में बढ़ोतरी

आरबीआई ने कहा कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 7.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.11 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक, आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास भारत की आरक्षित जमा 3.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.61 अरब डॉलर हो गई।

विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी का महत्व क्या?

मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत: विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था का संकेत है।

बढ़ती आयात क्षमता: यह भारत को अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करने और देश में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिक विदेशी मुद्रा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

बाहरी झटकों से बचाव: विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी झटकों, जैसे कि वैश्विक आर्थिक मंदी या मुद्रा में उतार-चढ़ाव से अर्थव्यवस्था की रक्षा करने में मदद करता है। भारतीय रुपये की स्थिति: यह भारतीय रुपये को अधिक स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे आयात और निर्यात दोनों के लिए अनुमान लगाना आसान हो जाता है।

बजाज फिनसर्व एएमसी ने केंद्रित रणनीति के साथ बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड लॉन्च किया

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि मिड और स्मॉल कैप श्रेणियों में अपने साथियों की तुलना में लार्ज कैप शेयरों में कम गिरावट आती है और वे अपने नुकसान की भरपाई तेजी से करते हैं। बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड के पास उच्च-दृढ़ स्टॉक चयन दृष्टिकोण के साथ एक केंद्रित पोर्टफोलियो होगा। उच्च सक्रिय शेयर रणनीति को नियोजित करके लंबी अवधि में बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन देने का लक्ष्य है।

केंद्रीय बजट 2024-25 रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग की थीम के साथ भारत को विकसित भारत बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप का निर्माण किया है: फियो अध्यक्ष, श्री अश्विनी कुमार

नई दिल्ली। एजेंसी

फियो के अध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट ने किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया है। इसने देश को न केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखने, बल्कि इसे विकसित भारत के रूप में विकसित करने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप भी बनाया है। श्री अश्विनी कुमार ने कहा कि रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग की बजट थीम आयात प्रतिस्थापन के प्रयास के अलावा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देगी।

फियो अध्यक्ष ने कहा कि कृषि अनुसंधान में बदलाव करके कृषि में उत्पादकता और लचीलेपन को प्राथमिकता देना इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने की कुंजी है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ के बजट प्रावधान के साथ झींगा उत्पादन और निर्यात और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ प्राकृतिक खेती से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन योजना विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

फियो अध्यक्ष ने कहा कि बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम केंद्रित विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें एमएसएमई के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता को कवर करने वाला एक पैकेज तैयार किया गया है ताकि उन्हें बढ़ने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिल सके। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में और विशेष रूप से तनाव की अवधि के दौरान एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना बजट में घोषित एक और पहल है जो व्यापार और उद्योग को बड़े पैमाने पर स्थिति और कोविड -19 महामारी जैसी चुनौतियों से बाहर निकलने में मदद करेगी। इसके अलावा, एमएसएमई को अपने व्यापार प्राप्तियों को नकदी में परिवर्तित करके अपनी कार्यशील पूंजी को अनलॉक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों के टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ करने का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। श्री अश्विनी कुमार ने कहा कि इसके अलावा, एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना और एनएबीएल मान्यता के साथ 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता व्यवसायों के लिए एक वरदान है।

फियो प्रमुख ने दोहराया कि पीपीपी मोड के तहत ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की स्थापना से एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने और एक ही छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे जिलों को निर्यात केंद्र और सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजनाओं के रूप में बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी, जिससे जीआई उत्पादों और हस्तशिल्प वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा, कारीगरों, शिल्पकारों और किसानों के लाभ के लिए ऐसे उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे उनकी आय कई गुना बढ़ जाएगी।

फियो प्रमुख ने यह भी कहा कि स्वामित्व, पट्टे और फ़्लैगिंग सुधारों का प्रस्ताव, जिसे भारतीय शिपिंग उद्योग की हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए लागू किया जाएगा और अधिक रोजगार पैदा करेगा, सरकार द्वारा एक अनुकूल पहल है, जैसा कि फियो ने अपने प्री - बजट परामर्श.के दौरान प्रस्तावित किया था। पूर्वोदय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के सृजन को कवर करेगा और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र को विकास का इंजन बनाएगा।

श्री अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि बजट में प्रमुख घोषणाओं में से एक 'हार्ड टू एबेट' उद्योगों अर्थात जिन उद्योगों के लिए अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना कठिन है,को 'ऊर्जा दक्षता' लक्ष्य से 'उत्सर्जन लक्ष्य' तक ले जाने के लिए एक रोडमैप है, जिसके लिए जल्द ही उचित नियम तैयार किए जाएंगे। उद्योगों को वर्तमान 'परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड' मोड से 'इंडियन कार्बन मार्केट' मोड में लाया जाएगा। पीतल और सिरेमिक सहित 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों का निवेश-ग्रेड ऊर्जा ऑडिट और उन्हें ऊर्जा के स्वच्छ रूपों में स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय सहायता और ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन को अगले चरण में अन्य 100 क्लस्टरों में भी दोहराया जाएगा, जिससे वे विकसित दुनिया द्वारा प्रस्तावित सीबीएएम और अन्य पर्यावरणीय मानदंडों से निपटने के लिए भविष्य में तैयार हो सकें।

फियो प्रमुख ने यह भी कहा कि चमड़ा और कपड़ा क्षेत्रों में निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, बत्तख या हंस से वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी में कमी और चमड़े तथा कपड़ा वस्त्र, जूते और अन्य के निर्माण के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में वृद्धि करना चमड़े की वस्तुओं के साथ-साथ कच्ची खाल, खाल और चमड़े पर निर्यात शुल्क संरचना का सरलीकरण और युक्तिकरण ऐसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान निर्यात क्षेत्र के लिए एक और बूस्टर है।

फियो अध्यक्ष ने आगे दोहराया कि बजट में की गई घोषणाएं जल्द ही हमारे देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगी और आने वाले समय में भारत को 'विकसित भारत' बनाने में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगी, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित होगा, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ होगा।

मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवारों को रेल मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी, बजट के तुरंत बाद किया ऐलान

नई दिल्ली। एजेंसी

रेल मंत्री ने बताया है कि एसी और गैर एसी कोचों का अनुपात आम तौर पर 1/3 और 2/3 रहा है। उस अनुपात को बनाए रखा गया है। गैर एसी यात्रा की मांग अब बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 के पहले बजट को पेश कर दिया। इस बजट के दौरान सभी की नजरें रेलवे को लेकर होने वाली घोषणाओं पर लगी रहीं। हालांकि, बजट के दौरान सिर्फ एक बार ही रेलवे शब्द का जिक्र किया गया, लेकिन बजट खत्म होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करोड़ों रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज दी है। रेल मंत्री ने मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवारों को खुशखबरी देते हुए बताया है कि रेलवे अभी ढाई हजार नॉन-एसी कोच बना रहा है और अगले तीन सालों में दस हजार और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य यह है कि कम आय वाले परिवार और मिडिल क्लास किफायती कीमत पर सुरक्षित यात्रा कर सकें। ट्रेनें हजार किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 450 रुपये की लागत पर विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रही हैं। 'एनडीटीवी' से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल 2014 से पहले रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय पर निवेश 35,000 करोड़ रुपये के आसपास हुआ करता था। आज यह 2.62 लाख करोड़ रुपये है। यह रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय है। मैं रेलवे में इस तरह के निवेश के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूं। अगर हम 2014 से पहले के 60 सालों को देखें तो नई ट्रेनों की घोषणा बिना यह सुनिश्चित किए की जाती थी कि पटरियों में क्षमता है या नहीं। बिल्कुल लोकलुभावन उपाय किए गए जिनका रेलवे के बुनियादी ढांचे की स्थिति से कोई संबंध नहीं था। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया है कि नींव ठीक से तैयार हो। रेलवे ने पिछले कुछ सालों में वंदे भारत ट्रेनों पर काफी फोकस किया है। एक के बाद एक नई वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं। इसी पर जब रेल मंत्री से सवाल किया गया कि क्या रेलवे का फोकस वंदे भारत और फ्लैगशिप ट्रेनों पर रहेगा और गरीबों के लिए ट्रेनों पर नहीं तो मंत्री ने जवाब दिया कि दृष्टिकोण यह है कि हमारे पास एक बड़ा निम्न आय वर्ग है और हम उस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं और फिर एक आकांक्षी वर्ग है जो आगे आ रहा है। उस आकांक्षी वर्ग को भी संबोधित करने की जरूरत है, इसलिए हम दोनों को संबोधित कर रहे हैं। रेल मंत्री ने आगे कहा, 'एसी और गैर एसी कोचों का अनुपात आम तौर पर 1/3 और 2/3 रहा है। उस अनुपात को बनाए रखा गया है। गैर एसी यात्रा की मांग अब बढ़ गई है। अधिक से अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग गैर एसी सेगमेंट के लिए यात्रा सेवाओं की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमने एक विशेष अभियान चलाया है। हम 2,500 गैर-AC कोच बना रहे हैं और आने वाले तीन वर्षों में हम नियमित उत्पादन कार्यक्रम के अलावा 10,000 अतिरिक्त गैर-AC कोच बनाएंगे।'

रेल बजट 2024-25 में मध्य प्रदेश को 14,738 करोड़ रूपये का बजट आवंटन

सेफ्टी, कवच, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यात्री सुविधाओं पर विशेष फोकस

रतलाम। एजेंसी

केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दिनांक 23.07.2024 को प्रस्तुत बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा करते हुए बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए रणनीति में बदलाव कर अधिकाधिक निवेश पर बल दिया गया है जिससे रेलवे पर संरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2024-25 में रेलवे को 2,62,200 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है जो अभी तक का सर्वाधिक है। रेलवे में संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में 108 हजार करोड़ करोड़ रूपए का आंवटन किया गया है। माननीय रेलमंत्री ने संरक्षा को रेलवे का महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि गत वर्ष भारतीय रेलवे पर संरक्षा सम्बंधित मदों पर 98 हजार करोड़ रूपए का व्यय किया गया है।

मध्य प्रदेश को मिला 14738 करोड़ रूपये का बजट आवंटन

श्री अश्विनी वैष्णव, रेलमंत्री ने मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश राज्य देश का हृदय प्रदेश है। वर्ष 2009-14 तक मध्य प्रदेश को औसत बजट मात्र 632 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष मिलता था जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 के बजट में 14,738 करोड़ रूपए आवंटन किया गया है जो अभी तक का सर्वाधिक बजट आवंटन है। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेल कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 81 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत रेल लाइनों को विद्युतीकरण हो गया है। 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पर 1062 फ्लाईओवर और रोड़ अण्डर ब्रिज का निर्माण किया गया है। रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं को पर्याप्त बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बात कही। रेलवे में सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण निधि निर्धारित की गई है। संरक्षा के बारे में बताते हुए माननीय रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे पर कवच प्रणाली से संबंधित कार्यों को पूरा कर लिया गया है और आरडीएसओ द्वारा कवच 4.0 वर्जन को अंतिम रूप दिया गया है, अब इस अत्यानुधिक कवच प्रणाली को विभिन्न रेल मार्गों पर लगाए जाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होने बताया कि कवच प्रणाली को स्थापित करने में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, टावर लगाने, डाटा सेंटर स्थापित करने और आरएफआईडी डिवाइस लगाने जैसे कार्य किए जाते है, जिससे इसमें समय लगता है। भारतीय रेलवे पर लगभग 3000 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच प्रणाली लगाई जा चुकी है।

ओल्ड बनाम न्यू टैक्स रिजीमः आपको किस टैक्स का विकल्प चुनने पर होगा फायदा?

नई दिल्ली। एजेंसी

लोकसभा में मंगलवार को पेश हुए आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये स्लैब छह लाख रुपये तक था. न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी कुछ बदलाव किया गया है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50 हज़ार से बढ़ाकर 75 हज़ार रुपए कर दिया है।

इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को अधिकतम 17,500 रुपए तक का फायदा होगा. हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी।

इसका हिसाब किताब कुछ इस तरह है।

तीन लाख रुपये तक की कमाई पर तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। तीन लाख से 7 लाख रुपये तक पर टैक्स दर 5 फ़ीसदी है यानी इस स्लैब के 4 लाख रुपये पर 5 फ़ीसदी की दर से टैक्स हुआ 20 हज़ार रुपये।

सेक्शन 87ए के तहत ये 20 हज़ार रुपये का टैक्स सरकार माफ़ कर देती है यानी कोई टैक्स नहीं देना है।

सैलरीड क्लास को 75 हज़ार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा दिया गया है, तो कुल मिलाकर 7 लाख 75 हज़ार रुपये तक की इनकम हो गई टैक्स फ्री।

10 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा एक भी रुपया टैक?स

अगर आप 10 लाख रुपये की कमाई पर पूरा पैसा बचाना चाहते हैं तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में ही संभव है।

हालाँकि इसके लिए कई तरह की छूट को हासिल करने के लिए निवेश करना होगा। लेकिन अगर निवेश नहीं कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी स्लैब के मुताबिक़ ही टैक्स देना होगा।

ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे बचा सकते हैं टैक्स?

सरकार ने इस व्यवस्था के तहत 50 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। यानी 10 लाख रुपये में से 50 हज़ार रुपये घटा दें तो अब टैक्स के दायरे में आने वाली रक़म साढ़े 9 लाख रुपये रह जाएगी।

निवेश करके बचा सकेंगे डेढ़ लाख रुपए पर टैक्स

इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं. इंफ्लॉई प्रॉविडेंट फंड यानी ईपीएफ़, पीपीएफ़, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, पाँच साल के फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है। इनमें से किसी एक में या कई स्कीम्स में कुल मिलाकर अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ये किया है, तो अब साढ़े 9 लाख रुपये में से 1.50 लाख रुपये और घटा दें. अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 8 लाख रुपये रह जाएगी।

होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक की टैक्स बचत

होम लोन ले रखा है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं.

आयकर के सेक्शन 24बी के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी कर योग्य आय में से घटा दें। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 6 लाख रुपए रह जाएगी।

हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च़ भी टैक्स फ्री

आयकर के सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर 25 हज़ार रुपए तक की टैक्स बचत कर सकते हैं. इस हेल्थ इंश्योरेंस में खुद, पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए.

इसके अलावा अगर माता-पिता सीनियर सिटीजन के दायरे में आते हैं, तो फिर उनके नाम पर मेडिकल पॉलिसी खरीदकर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट ली जा सकती है। यानी इस मद में कुल मिलाकर 75 हज़ार रुपये की रक़म टैक्स फ्री हो सकती है।

अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5 लाख 25 हज़ार रुपये रह जाएगी।

नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश पर 50 हज़ार की टैक्स छूट

अगर अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं, तो आयकर के सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत अतिरिक्त 50 हज़ार रुपये की छूट मिल जाएगी। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 4 लाख 75 हज़ार रुपये रह जाएगी।

अब मिलेगा 87 ए का फ़ायदा

5 लाख रुपये तक की आय पर लगने वाले 12,500 रुपये के टैक्स पर छूट है, यानी पाँच लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में क्योंकि अब आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख 75 हज़ार रुपये है, इसलिए आप पर टैक्स देनदारी नहीं बनती है।

न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख की कमाई पर कितना देना होगा टैक्स?

भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है, फिर भी 10 लाख की कमाई पर आपको टैक?स देना ही पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत किसी भी तर के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल सकता।

आपने न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुना है तो अब 50 हज़ार की जगह 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी कुल टैक्सेबल इनकम 9 लाख 25 हज़ार रुपए होगी। पहले जिन्हें इस आय पर 52,500 रुपये की टैक्स देनदारी बनती थी, उन्हें अब सिर्फ़ 42,500 रुपये टैक्स चुकाना होगा। यानी नई टैक्स रिजीम में सालाना 10 लाख रुपये तक की आमदनी वाले 10 हज़ार रुपए और बचा लेंगे।

नई टैक्स रिजीम में क्या बदला?

छह टैक्स स्लैब, 30% का अधिकतम टैक्स

पुराना स्लैब	पुरानी दर	नए स्लैब	नई दर
3 लाख	0%	3 लाख	0%
3-6 लाख	5%	3-7 लाख	5%
6-9 लाख	10%	7-10 लाख	10%
9-12 लाख	15%	10-12 लाख	15%
12-15 लाख	20%	12-15 लाख	20%
15 लाख से अधिक	30%	15 लाख से अधिक	30%

'कश्मीरी नीलम' की चमक दुनिया देखेगी, निर्यात बढ़ाने के लिए यह हुआ है काम

श्रीनगर। एजेंसी

कश्मीरी नीलम की चमक अब दुनिया देखेगी। जी हां, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले संगठन रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने इस दिशा में मजबूत पहल की है। संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिनों इस बारे में कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) और ऑल कश्मीर गोल्ड डीलर एसोसिएशन (KGDA) के प्रमुख सदस्यों और यहां के रत्न और आभूषण व्यापार के सदस्यों के साथ विशद चर्चा की।

निर्यात वाले आभूषणों में बढ़ेगा कश्मीरी नीलम का उपयोग

जीजेईपीसी के अध्यक्ष विपुल शाह ने बताया कि कश्मीर के ट्रेड मेंबर्स के साथ उनकी बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई। वह निर्यात वाले आभूषणों में कश्मीरी नीलम की प्रमुखता बढ़ाने और स्थानीय कारीगरों को उन्नत कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह पहल रत्न और आभूषण क्षेत्र को मजबूत करने, इसके विकास के लिए निरंतर कोशिश करने, अंतरराष्ट्रीय मान्यता और क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के हमारे मिशन के साथ जुड़ी हुई है। हम कश्मीरी ट्रेड मेंबर्स को उनकी भागीदारी के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे भी इसी तरह के उपयोगी सहयोग की उम्मीद करते हैं।

कई देशों में कश्मीरी आभूषण लोकप्रिय

शाह का कहना है कि ईरानी और मध्य एशियाई समुदायों के बीच कश्मीरी आभूषणों को लेकर जो दिलचस्पी है, उसके महत्व को अच्छी तरह पहचानते हैं। कश्मीरी व्यापार के साथ हमारे सहयोग का उद्देश्य इस उत्कृष्ट शिल्प कौशल की वैश्विक पहुंच और प्रभाव का विस्तार करना है। आधुनिक डिजाइन के साथ पारंपरिक कश्मीरी कलात्मकता के अनूठे मिश्रण ने इन क्षेत्रों के खरीदारों को आकर्षित किया है, जो प्रत्येक आभूषण में कुशल कारीगरी और खूबसूरती की बहुत सराहना करते हैं।

बढ़ेगा कश्मीरी ज्वैलरी का निर्यात

जीजेईपीसी के उपाध्यक्ष किरीट भंसाली ने कश्मीरी क्षेत्र के रत्न और आभूषण व्यापार को वैश्विक बाजारों में विस्तारित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि दुबई में आईजेईएक्स (IJEX) के माध्यम से यहां के प्रोडक्ट को दुनिया भर के बाजार में प्रोमोट किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दुबई में जीजेईपीसी का आईजेईएक्स साल भर चलने वाला बी2बी इवेंट प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से जीजेईपीसी के सदस्य अपने प्रॉडक्ट्स का प्रदर्शन कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यूएई (UAE) में उनकी बाजार उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

जमीन की खरीद-फरोख्त में अब नहीं होगी नींद हराम, सरकार कर रही पक्का इंतजाम

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया में ज्यादातर झगड़े जमीन को लेकर होते हैं। साथ ही जमीन की खरीद-फरोख्त में भी फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती रहती है। कई बार एक ही प्लॉट कई लोगों को बेच दिया जाता है। लेकिन अब सरकार इससे निपटने के लिए पक्का इंतजाम करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्लॉट के लिए 'भू-आधार' नंबर देने की घोषणा की है। यह आधार की तरह एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। साथ ही 2027 तक शहरी इलाकों में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की योजना है। इस रिफॉर्म को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देगी। माना जा रहा है कि इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट फ्लो और एग्रीकल्चर सर्विसेज से जुड़ी दूसरी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे कस्बों और शहरों में जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी रोकने और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी।सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि से संबंधित सुधार और एक्शन के दायरे में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और अर्बन प्लानिंग, यूसेज और बिल्डिंग्स से जुड़े नियम आएंगे। उन्होंने कहा कि उचित वित्तीय सहायता के माध्यम से इन्हें अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े कामों में सभी लैंड पार्सल के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) या भू-आधार देना, जमीन से जुड़े मैप्स का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मैप सब-डिवीजन्स का सर्वे, लैंड रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों की रजिस्ट्री से लिंक करना शामिल होगा।

आईटी-बेस्ड सिस्टम

योजना के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी रेकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अपडेटिंग और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक आईटी-आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। बजट से एक दिन पहले पेश इकनॉमिक सर्वे में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को तेजी के साथ डिजिटल करने का आह्वान किया था।

आइना भी कर सकता है भाग्य को खराब, घर में किस जगह पर लगाना चाहिए शीशा, जानें

घर में मौजूद हर वस्तु में ऊर्जा होती है किसी चीज में सकारात्मक और किसी में नकारात्मक. लेकिन पॉजीटिव रिजल्ट पाने के लिए उन चीजों का सही जगह पर होना बहुत जरुरी होता है, ऐसा करने से घर में बरत पड़ती है और घर में खुशियों का वास होता है. घर या ऑफिस में वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत जरुरी माना गया है. ऐसा करने से साकात्मक ऊर्जा का वास होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार शीशा घर में कहा होना चाहिए. इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए की घर में शीशा लगाने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को चुनना चाहिए. वास्तु के अनुसार शीशा लगाने के लिए इस दिशा को उपयुक्त माना गया है.

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

वास्तु शास्त्र में उत्तर या पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है. इस दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है. इसीलिए इस दिशा में शीशा लगाने से घर में पैसा का फ्लो बढ़ता है.

उत्तर या पूर्व दिशा में शीशा लगाने से घर में शांति का वास होता है. इस बात का खास ख्याल रखें की उत्तर या पूर्व दिशा से अर्थ है कि शीशा इस तरह लगाना चाहिए कि देखने वाले का चेहरा पूर्व या उत्तर की ओर रहे. घर में गलत जगह लगाया गया शीशा आपके भाग्य को खराब कर सकता है. इसीलिए शीशा लगाने से पहले इन सभी नियमों का पालन जरुर करें.

किस तरह का शीशा लगाना चाहिए

अगर आप भी घर के उत्तर या पूर्व दिशा में शीशा लगा रहे हैं तो गोल शीशा लगा सकते हैं.

शीशा कहां नहीं लगाना चाहिए

शीशा कभी भी आपके बिस्तर के ठीक सामने नहीं होना चाहिए. सुबह उठते ही शीशे के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है.

शीशा कभी भी पश्चिम या दक्षिण की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए. इस दिशा में शीशा लगाने से घर में अशांति बनी रहती है.

किचन या रसोई घर के ठीक सामने शीशा नहीं लगाना चाहिए, या किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

शीशा लगाते समय या खरीदते समय इस बात का ख्याल रखें कि शीशा साफ हो, टूटा हुआ शीशा नहीं लगाना चाहिए. घर में शीशा गंदा होने से परिवार के सदस्य तरक्की नहीं कर पाते.

शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय चंदन से 'राम' नाम क्यों लिखा जाता हैं, जानिए महत्व

पं. श्री रमेशचंद व्यास
(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषयाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

सावन के माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तुएं पूजा के दौरान अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को सावन माह में भक्त सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ, बेलपत्र अर्पित आदि सब करते हैं, बेलपत्र अर्पित करना बहुत लाभकारी माना जाता हैं। बेलपत्र भगवान को बहुत प्रिय हैं, लेकिन बेलपत्र अर्पित करने से पहले चंदन से राम-राम लिखना बेहद शुभ माना गया हैं। सावन में शिवलिंग को बेलपत्र चढ़ाना और जल से अभिषेक करने से भी भगवान शिव अतिप्रसन्न होते हैं।

बेलपत्र पर 'राम' नाम का महत्व

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, राम नाम लिखे हुए बेलपत्र को चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने ही सबसे पहले भगवान शिव को राम-राम लिखे बेलपत्र अर्पित किए थे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको पत्नी के तौर पर स्वीकार किया था।पार्वती माता ने उन्हें खुश करने के लिए ही बेलपत्र पर राम नाम लिख शिव को अर्पित किया था। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति चंदन से बेलपत्र पर राम नाम लिखतें है, तो शिव जी की कृपा उस भक्त पर बनी रहती है और धन-धान्य की प्राप्ति भी होती हैं। अगर बेलपत्र नहीं हो तो अक्षत से भी शिव को पूजा जा सकता हैं। वहीं स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर किसी कारणवश बेलपत्र नहीं मिल पाए तो पूर्व से चढ़ाए बेलपत्र को धोकर भी शिव को अर्पित कर सकते हैं।सावन में बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा को अधूरा माना जाता हैं। तीन पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना बहुत शुभ होता है और बेलपत्र को अर्पित करते समय इसकी चिकने सतह की तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र के अलावा आप भांग, धतूरा, मदार का फूल, आदि भी अर्पित कर सकती हैं। यह भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं।

बेलपत्र अर्पित करते समय करें मंत्र का जाप

भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र कटा-फटा नहीं होना चाहिए। उसमें तीन पत्तियां जरूर होनी चाहिए। राम-राम लिखे 12 बेलपत्र को बारी-बारी से भगवान शिव को अर्पित करें और हर बार ओम नमः शिवाय शिवाय नमः मंत्र का जाप करें।

कंवडिये क्यों बोलते हैं 'बोल बम बम भोले' बेहद खास है वजह, जानें

पंडित कपिल पाराशर
ज्योतिष आचार्य
वास्तु विशेषज्ञ
6261493070

इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई 2024 से शुरू होगी. श्रावण के पूरे महीने कांवड़िए महादेव को प्रसन्न करने के लिए मीलों पैदल चलकर यात्रा करते हैं और कांवड़ में गंगा नदी से जल भरकर लाते हैं और सावन शिवरात्रि पर उस जल से अभिषेक करते हैं. कांवड़ यात्रा में बोल बम-बम भोले का नारा चारों और गूंजता है. मान्यता है कि बोल बम नारा लगाने से यात्रा कष्टमय नहीं होती. भोलेनाथ कांवड़ियों की यात्रा मंगलमय करते हैं. बोल बम में बम शब्द ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं ओमकार का प्रतीक माना गया है. बोलबम सिद्ध

मंत्र है. इसे बोलने से श्रद्धालु के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो भक्तों को शक्ति प्रदान करता है. कहते हैं कि जब हनुमान जी को शक्ति की आवश्यकता होती थी तो वो राम नाम का जाप करते थे उसी तरह कांवड़िए थका हुआ महसूस करते हैं या फिर दूसरे कांवड़ियों में जोश भरना होता है तो वह बोल बम का जयकारा लगाते हैं. 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि है इस दिन कांवड़िए कांवड़ में जो जल भरकर लाते हैं उसके जलाभिषेक करते हैं.

इस साल सावन 19 अगस्त 2024 तक रहेगा. ऐसे में इस बार 5 सावन सोमवार आएंगे. सावन सोमवार, सावन प्रदोष व्रत, सावन शिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र अर्पित करें, जलाभिषेक करें.

सावन में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व

जानें विधि और पूजा सामग्री, होंगी महाकाल की कृपा

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का एक विशेष माह होता है, सावन के माह में रुद्राभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रिय होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाएं रखते हैं। भगवान शिव को समर्पित माह सावन की शुरूआत 22 जुलाई से होकर 19 अगस्त तक हैं। जानिए रुद्राभिषेक को किस विधि से करने पर भोलेनाथ का मिलता हैं आशीर्वाद। भक्त इस दौरान लोग कई प्रकार से शिवलिंग की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। रुद्राभिषेक का आयोजन करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी वजह से लोग इस दौरान पूरे भक्ति भाव से पूजन और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।

सावन में रुद्राभिषेक का महत्व

सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती हैं। रुद्राभिषेक के माध्यम से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं तो जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती हैं। सावन महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है और इस दौरान शिव पूजन बाहर लाभकारी होता हैं। इस दौरान जो भी रुद्राभिषेक करता है उसके घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं। यदि आपके घर में कोई भी बाधा है तो वो दूर होती है और आपके करियर से जुड़ी समस्याओं का भी अंत होता है मान्यता है कि यदि संतान की सेहत के लिए चिंता बनी रहती है तो आपके लिए यह अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सावन शिवरात्रि -2 अगस्त, नागपंचमी - 9 अगस्त इस साल रुद्राभिषेक के लिए सावन के ये पूरे माह के साथ ही 2 दिन सबसे खास हैं। यदि संभव हो तो इन्हीं तिथियों में रुद्राभिषेक करें।

सावन में रुद्राभिषेक की विधि

जिस दिन घर में या मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं आपको प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। पूजा के लिए तैयार होने से पहले स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है। स्नान के बाद साफ-सुथरे वस्त्र पहनें। आपको पवित्र शरीर और मन से पूजन करना चाहिए। पूजा के लिए एक पवित्र स्थान चुनें। इसे अच्छी तरह से साफ करें और वहां एक आसन बिछाएं। इस पर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को स्थापित करें । पूजा स्थल को फूलों से सजाएं और रुद्राभिषेक पूजा आरंभ करें। मान्यता है कि शिव जी को जल का अभिषेक सबसे ज्यादा प्रिय होता है।

सावन में रुद्राभिषेक की पूजा सामग्री

यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर तैयार किया जाता है।

पवित्र जल के रूप में हम शिवलिंग के स्नान के लिए गंगाजल का उपयोग करते हैं।

पूजा स्थल पर एक कलश रखें, जिसमें पानी भरकर आम के पत्तों से सजाएं।

बेल पत्र, आम के पत्ते और ताजे फूल भगवान शिव को अर्पित करने के लिए जरूर रखें।

पूजा के दौरान घी का दीपक जलाएं।

चावल के दाने, जिन्हें पूजा के दौरान भगवान को अर्पित किया जाता है।

पूजा स्थल को सुगंधित बनाने के लिए।

मिठाई या फल, जो भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं।

श्रृंगी एक ऐसा यंत्र है जिससे शिवलिंग का जलाभिषेक रुद्राभिषेक पूजा में किया जाता है।

आखिर लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर और सेबी चीफ ने भी जता दी चिंता

नई दिल्ली। एजेंसी

समाचार पत्रों में पिछले दिनों ही खबर आई थी। दिल्ली में रहने वाले शशि भूषण ने पिछले साल एक म्यूचुअल फंड स्कीम (शर्ल्ट इल्ह् एम्पस) में एक लाख रुपये का निवेश किया था। साल भी ही उनकी रकम बढ़ कर 1.70 लाख रुपये हो गई। मतलब कि 70 फीसदी का रिटर्न। शशिभूषण को इतना रिटर्न कहीं जुए या सट्टे से नहीं बल्कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से मिली है।

क्या यह गैरकानूनी है?

यहां सवाल उठता है कि एक ही साल में इतना रिटर्न देने वाली ये स्कीम क्या गैर-कानूनी है? इसका जवाब है नहीं। यह सब कानूनी है। दरअसल, शेयर बाजार सदा से ही बढ़िया रिटर्न देती रहा है। लेकिन पहले इस तक पहुंच बहुत कम लोगों की थी। लेकिन अब म्यूचुअल फंड की पहुंच गांव-गांव तक हो गई है। लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं। अब उन्हें अहसास हो रहा है कि अपनी जमा-पूंजी पर बेहतर रिटर्न पाना है तो उन्हें शेयर बाजार में निवेश करना होगा।

बैंक एफडी का क्या हाल

कुछ लोगों को अहसास होने लगा है कि उसने बैंक एफडी के चक्कर में शेयर बाजार से दूरी बनाकर गलती कर दी। अब वह अपनी बचत ही नहीं बल्कि प्रॉविडेंट फंड का पैसा भी शेयर बाजार में लगाने को तैयार हैं। उन्हें यकीन है कि म्यूचुअल फंड (MF) में रिटर्न ज्यादा मिलेगा। उन्हें यह भी पता चला चुका है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न महंगाई का मुकाबला नहीं कर पाता।

इनके माथे पर शिकन

इस समय बैंक एफडी के मुकाबले म्यूचुअल फंडों में पैसा ज्यादा तेजी से जमा हो रहा है। इससे कुछ लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। अब रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ही देखिए। उन्होंने शुक्रवार को ही बैंकों में घटते डिपॉजिट पर चिंता जताई है। उनके साथ साथ शेयर बाजार के नियामक सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच भी कहा कि घरेलू बचत को फ्यूचर ऐंड ऑप्शन में लगाया जा रहा है।

बैंक एफडी या म्यूचुअल फंड

निवेश गुरु विश्वदीप पराशर का कहना है कि बैंक एफडी एक सिक्योर प्रॉडक्ट है। इसमें घाटे की संभावना कतई नहीं है। लेकिन यह निवेशक को पर्याप्त रिटर्न भी नहीं दिलवाता। इस समय तो यह महंगाई की दर या इन्फ्लेशन रेट को भी पछाड़ नहीं पाता। इस समय एसबीआई में पांच साल के लिए एफडी कराएं तो करीब सात फीसदी का रिटर्न मिलता है। वहीं म्यूचुअल फंड में करीब 12 फीसदी का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। बैंक एफडी पर आयकर की दर भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा है। इसलिए लोग बैंक एफडी के मुकाबले म्यूचुअल फंड को तवज्जो दे रहे हैं।

क्या म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की कमी है?

पराशर बताते हैं कि अब म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं रही है। आप अपने फंड को रिडीम करना चाहते हैं तो दिन में दोपहर बाद तीन बजे तक आप ऐसा करें। दूसरे कार्य-दिवस में आपके फंड का पैसा आपके अकाउंट में होगा। उनका कहना है कि जैसा शेयर बाजार में होता है, वैसी ही लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी होती है।

भारत में तेजी से बढ़ रही है फोल्डेबल स्मार्टफोन की मांग

सैमसंग के मोबाइल बिजनेस हेड टीएम रोह

गुरुग्राम। आईपीटी नेटवर्क

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक है और सैमसंग के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। यह कहना है दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एक सीनियर एक्जीक्यूटिव का। भारत में बिकने वाले लगभग 80% स्मार्टफोन की कीमत 30,000 रुपये से कम है, लेकिन अब पहले से ज्यादा उपभोक्ता प्रीमियम स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, जिससे फोल्डेबल जैसे खास प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल एक्सपीरियंस बिजनेस के प्रेसिडेंट और हेड टीएम रोह ने कहा, 'भारतीय बाजार उन बाजारों में से एक है जहां फोल्डेबल फोन्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा खास गैलेक्सी फोल्डेबल्स हैं। हमें उम्मीद है कि इस साल बाजार में मांग बढ़ेगी और भारतीय ग्राहक गैलेक्सी एआई के साथ नए गैलेक्सी Z फ्लिप6 और गैलेक्सी Z फोल्ड6 को अपनाएंगे जिन्हें फोल्डेबल स्मार्टफोन पसंद करने वालों के लिए बनाया गया है।' सैमसंग के हाल ही में लॉन्च किए गए गैलेक्सी Z फोल्ड6 और Z फ्लिप फोल्डेबल स्मार्टफोन ने भारत में शानदार शुरुआत की है और मात्र 24 घंटों में ही पिछली जनरेशन के फोल्डेबल स्मार्टफोन की तुलना में इनकी 40% ज्यादा प्री-बुकिंग हो चुकी हैं। छठी जनरेशन के गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी एआई पर चलते हैं जो सैमसंग के एआई टूल्स का एक सेट है। यह कम्युनिकेशन की बाधाओं को तोड़ने और उपभोक्ताओं की रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। टीएम रोह ने कहा कि सैमसंग बड़े पैमाने पर मोबाइल एआई को आम लोगों तक पहुंचा रहा है और साल के अंत तक 200 मिलियन गैलेक्सी डिवाइस में गैलेक्सी एआई को इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गैलेक्सी Z फोल्ड 6 और गैलेक्सी Z फ्लिप 6 बेहतरीन फोल्डेबल डिज़ाइन और गैलेक्सी एआई के साथ सबसे शक्तिशाली गैलेक्सी एआई फोल्डेबल हैं।

कोस्टा कॉफी के भारतीय बरिस्ता ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के आधिकारिक पार्टनर के रूप में बिखेरेंगे अपना जलवा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोस्टा कॉफी ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 का आधिकारिक पार्टनर होगा। पूरी दुनिया में भारतीय बरिस्ता को केंद्र में लाने और कॉफी की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। छह कियोस्क और 110 से भी अधिक सेल्फ-सर्व पैक्टो मशीनों के साथ, छह देशों की 130 कोस्टा कॉफी टीम पूरे पेरिस में बने सात वेन्यू में अपना हुनर दिखायेंगी। ये टीम प्रशंसकों तथा खिलाड़ियों को ठंडे तथा गर्म पेय का बेहतरीन अनुभव कराएगी।

इस साझेदारी के तहत कोस्टा कॉफी तीन बेहतरीन भारतीय बरिस्ताः अमीर फेयज़, मल्लिका त्रिपुरा और अभिषेक कुमार को पेश कर कर रही है। अपने कौशल को थोड़ा और धार देने तथा कोस्टा कॉफी के टीम वर्क व उत्कृष्टता के मूल्यों को पेश करने के लिए इन्होंने काफी मुश्किल ट्रेनिंग की है। उन जगहों पर पूरा कामकाज बेहतर तरीके से हो पाए, इसके लिए टीम के सदस्य पूरी तरह मुस्तैद हैं और खिलाड़ियों तथा दर्शकों के लिए कॉफी की विशेष मास्टर क्लास भी आयोजित की जाएगी। ओलंपिक के रोमांच को थोड़ा और बढ़ाने के लिए कोस्टा कॉफी टीम के चुनिंदा सदस्यों को ओलंपिक गेम्स में मशाल थामने का भी शानदार मौका दिया जाएगा।

विनय नायर, जनरल मैनेजर, इंडिया एंड इमर्जिंग इंटरनेशनल, कोस्टा कॉफी, कोका-कोला कंपनी, का कहना है, 'हम ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के आधिकारिक कॉफी पार्टनर बनकर काफी खुश हैं। इससे ना केवल हमारे भारतीय बरिस्ताओं को अपने कौशल और कलात्मकता को इतने प्रतिष्ठित मंच पर दिखाने का मौका मिलेगा, बल्कि हमारी प्रतिभाशाली टीम के सदस्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी झलकेगी। इतना बेहतरीन अवसर प्रदान कर हम उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम हर तरह की संस्कृति को अपनाने और उत्कृष्टता को लेकर उनकी लगन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।''

मानसून के मौसम में देखभाल आपके हीरों की चमक बनाए रखने के लिए डी बीयर्स फॉरएवरमार्क के एक्सपर्ट टिप्स

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मानसून के साथ ही एक ताज़ा बदलाव तो आता है, लेकिन मानसून के साथ आई नमी आपके चमकते हीरों को नुकसान पहुंचा सकती है। डी बीयर्स फॉरएवरमार्क, एथिकल डायमंड्स और शाश्वत सौंदर्य का दूसरा नाम है। डी बीयर्स फॉरएवरमार्क यह सुनिश्चित करने के लिए एक्सपर्ट टिप्स बताते हैं, ताकि आप आपके कीमती रत्न पूरे सीजन में अपनी चमक बनाए रख सकें। इंदौर के फीनिक्स सिटाडेल मॉल और कल्पतरु ग्रैंड्योर में डी बीयर्स फॉरएवरमार्क एक्सक्लूसिव स्टोर पर फॉरएवरमार्क कलेक्शन उपलब्ध है।

मॉइश्चर यानी नमी से बचावः

सावधानी से सुखाएंः यदि आपकी डायमंड ज्वेलरी बारिश में भींग जाती है, तो इसे मुलायम, रोएं-मुक्त कपड़े से धीरे से थपथपाकर सुखाएं। ज्वेलरी को सुखाने के लिए, टिशू पेपर या कागज के तौलिये का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि इनसे ज्वेलरी की सतह पर खरोंच आ सकती है।

हवा में सुखाना (एयर ड्राइंग) सबसे अच्छा हैः हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने बचें, क्योंकि गर्मी सेटिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। अपने हीरे को वापस रखने से पहले उन्हें हवा में पूरी तरह सूखने दें।

सिलिका जेलः आपका मॉइश्चर बस्टरः अपने ज्वेलरी बॉक्स में सिलिका जेल पैकेट रखें। ये सुविधाजनक पैकेट अतिरिक्त नमी सोख लेते हैं और आपके हीरों पर कोई परत नहीं बनने देते हैं।

स्मार्ट स्टोरेज की रणनीतियाँः

अलग-अलग रखना सुरक्षित हैः डायमंड ज्वेलरी के प्रत्येक टुकड़े को एक अलग डिब्बे या थैली में रखें ताकि उन्हें एक-दूसरे से खरोंच न लगे।

कोमल स्पर्श देंः अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने हीरों को बटर पेपर या मलमल के कपड़े जैसी मुलायम और खरोंच न लगने वाली सामग्री में लपेट कर रखें।

सही ज्वेलरी बॉक्स चुनेंः अपने हीरे को धूल और नमी, तथा मानसून के मौसम के दौरान होने वाली आकस्मिक दिक्कतों से बचाने के लिए एक मजबूत ज्वेलरी बॉक्स चुनें, जिसमें हार्ड कवर लगा हो।

स्थायी चमक के लिए जरूरी दैनिक आदतेंः

निखार से ज्यादा सौंदर्य पर ध्यान देंः ज्वेलरी पहनने से पहले लोशन, परफ्यूम और मेकअप लगाते वक्त यह भी ध्यान रखें कि ये रसायन समय के साथ हीरे की चमक को फीका कर सकते हैं।

पसीने से बचाएंः देर तक चलने वाली गतिविधियों या खास तौर पर अपने वर्कआउट सेशन के दौरान काफी मात्रा में पसीना बहाते समय अपनी डायमंड ज्वेलरी को उतार दें।

जोश बनाए रखनाः

प्रोफेशनल सफाई महत्वपूर्ण हैः नियमित तौर पर घर पर ज्वेलरी की देखभाल आवश्यक है। डी बीयर्स फॉरएवरमार्क की सलाह है कि हर छह महीने से एक साल की अवधि में किसी अधिकृत जौहरी से प्रोफेशनल सफाई कराएं। इससे जमी हुई गंदगी हटेगी और हीरे की पुरानी असली चमक निखर कर सामने आएगी।

डी बीयर्स फॉरएवरमार्क के इन एक्सपर्ट टिप्स यानी सुझावों का पालन करने से, आपके हीरों की चमक मानसून के मौसम में भी बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना शाश्वत सौंदर्य बिखेरते रहेंगे। इसलिए, यह जानकर कि आपके कीमती हीरे पूरे मौसम में चमकते रहेंगे, पूरे विश्वास के साथ मानसून का स्वागत करें।

टाटा मोटर्स ने भारत की पहली एसयूवी कूपे टाटा कर्व को लॉन्च किया

मिड-एसयूवी कैटेगरी को नई परिभाषा दी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

एसयूवी डिज़ाइन में एक नए युग की शुरुआत करते हुए, भारत की अग्रणी ऑटोमोटिव निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने टाटा कर्व आईसीई और ईवी को लॉन्च किया। दमदार सिद्धांत, रूप और कार्यकुशलता की सोच पर आधारित कर्व भारत की पहली एसयूवी कूपे है। नए जमाने की एसयूवी टोपोलॉजी को प्रदर्शित करते हुए, कर्व में एक एसयूवी की मजबूती और उपयोगिता के साथ कूपे की खूबसूरती और स्पोर्टी पहचान का कलात्मक रूप से संयोजन किया गया है। 7 अगस्त को लॉन्च होने वाली, ऑल-न्यू कर्व टाटा मोटर्स की मजबूत मल्टी-पावरट्रेन रणनीति पर आधारित होगी। यह सबसे पहले अपने ईवी वर्जन में उपलब्ध होगी, जिसके बाद जल्द ही इसका आईसीई वर्जन भी आएगा।

अनावरण पर टिप्पणी करते हुए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, श्री शैलेश चंद्रा ने कहा, 'टाटा मोटर्स ने भारतीय एसयूवी सेक्टर में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके अलावा, हमने अनूठे डिजाइनों के माध्यम से बार-बार इस इस कैटेगरी में खलबली मचाई है। इस सेगमेंट के हमारे वाहन सड़क पर शानदार उपस्थिति के साथ-साथ मजबूत कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं। ओरिजनल सिएरा, सफारी, नेक्सन, पंच और हैरियर एसयूवी में इस डिजाइन आधारित मार्केट लीडरशिप के प्रमाण हैं। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए और अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए, हमने एक बार फिर से टाटा कर्व के रूप में भारत की पहली एसयूवी कूपे पेश करके उत्साह और आकांक्षाओं से भरी मिड एसयूवी कैटेगरी में गतिरोध को तोड़ा है।

मेटा द्वारा भारत के व्यवसायों के लिए मेटा वैरिफाइड सदस्यता शुरू की गई

सत्यापित बैज, बेहतर अकाउंट सपोर्ट, इंपर्सनेशन से सुरक्षा, और डिस्कवरी और कनेक्शन के लिए अतिरिक्त फीचर्स

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मेटा ने भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर व्यवसायों के लिए मेटा वैरिफाइड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं। कंपनी ने पिछले साल एक छोटे से परीक्षण के साथ व्यवसायों के लिए मेटा वैरिफाइड शुरू किया था, जिसका उद्देश्य यह जानना था कि मेटा किस प्रकार अपने ऐप्स पर व्यवसायों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे उपयोगी सदस्यता टूलकिट प्रदान कर सकता है। इससे पहले इस साल मेटा ने अपने प्रारंभिक परीक्षण का विस्तार कर एक सदस्यता प्लान को चार तक ले जाने की घोषणा भी की थी, और कंपनी ने पिछले साल व्हाट्सऐप पर व्यवसायों के लिए मेटा वैरिफाईड का लॉन्च कर इसे आगे बढ़ाया, जिसकी घोषणा इसकी कन्वर्सेशंस कॉन्फरेंस के दौरान की गई थी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस विस्तारित मेटा वैरिफाईड व्यवसायिक प्रस्तुति में बेहतर अकाउंट सपोर्ट, इम्पर्सनेशन सुरक्षा, और डिस्कवरी एवं कनेक्शन को सपोर्ट करने के लिए अतिरिक्त फीचर्स के साथ वैरिफाईड बैज शामिल है। ये फीचर्स मिलकर व्यवसायों को वृद्धि का अवसर प्रदान करते हैं और मेटा ऐप्स पर विस्तृत व्यवसायिक जरूरतों और गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं। मेटा की विस्तृत प्रस्तुतियाँ व्यवसायों से मिले फीडबैक और मार्केट रिसर्च पर आधारित हैं क्योंकि कंपनी ने यह परीक्षण पिछले साल शुरू कर दिया था। व्यवसाय के मालिकों ने मेटा को बताया है कि वो सत्यापित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इससे उन्हें विश्वसनीयता मिलती है और ग्राहकों का उन पर ज्यादा भरोसा स्थापित होता है, और वो उनके पास आते हैं। वैरिफाईड बैज़ मेटा वैरिफाईड की सदस्यता लेने के सबसे ज्यादा बताए गए कारणों में से एक है।

सैमसंग ने भारत में Z फोल्ड 6 और Z फ्लिप 6 स्मार्टफोन लॉन्च किये

गुरुग्राम। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने भारत में अपने छठी जनरेशन के फोल्डेबल स्मार्टफोन - गैलेक्सी Z फोल्ड6 और Z फ्लिप 6 के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। ये स्मार्टफोन्स गैलेक्सी एआई के अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे। नया गैलेक्सी Z फोल्ड6 और Z फ्लिप 6 गैलेक्सी एआई को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को मोबाइल का अनूठा अनुभव मिलेगा।

सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया के अध्यक्ष और सीईओ जेबी पार्क ने कहा, 'सैमसंग अपनी छठी जनरेशन के फोल्डेबल स्मार्टफोन- गैलेक्सी Z फोल्ड6 और Z फ्लिप 6 के साथ गैलेक्सी एआई के अगले अध्याय की शुरुआत करके खुश हैं। नए स्मार्टफोन कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में शानदार मोबाइल अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एआई-आधारित कनेक्टेड गैलेक्सी इकोसिस्टम के साथ, हमारे नए प्रोडक्ट आपको सशक्त बनाएंगे और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गैलेक्सी Z फोल्ड 6 और Z फ्लिप 6 दोनों का उत्पादन हमारी नोएडा फैक्ट्री में किया गया है।'

डी.पी. आभूषण लिमिटेड ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के दौरान नेट प्रॉफिट में 60% वृद्धि दर्ज की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

डी.पी. आभूषण लिमिटेड जो कि आभूषण उद्योग में 84 वर्षों की सुनहरी विरासत के साथ अपनी उच्चतम शुद्धता और डिजाइन स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंसी और प्रोडक्ट रेंज के लिए जाना जाता है, ने 30 जून 2024 को समाप्त हुई वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की। संतोष कटारिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहाः 'हम इस तिमाही के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन को रिपोर्ट करते हुए प्रसन्न हैं, जिसमें 7% की रेवेन्यू ग्रोथ और 60% की प्रॉफिट में बढ़ोतरी शामिल है। भोपाल स्टोर ने रेवन्यू में अहम भूमिका निभाते हुए साल दर साल 18३ की ग्रोथ हासिल की। उज्जैन और इंदौर ने भी क्रमशः 17% और 12% की ग्रोथ रेट के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे एक्सपेंशन प्लान के तहत हम वित्त वर्ष 25 में तीन नए शोरूम खोलने वाले हैं, जिनमें रतलाम, अजमेर और नीमच में निर्माण कार्य जारी है। यह विस्तार हमारे लौंग टर्म विज़न के साथ संरेखित होता है, जो वित्त वर्ष 24 में 8 से वित्त वर्ष 28 तक 20 स्टोर्स तक पहुंचने का है, जिससे हमारी बाज़ार के अंदर पहुँच में वृद्धि होगी। आगे देखते हुए, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है क्योंकि हम अपने बिजनेस ऑपरेशन को मजबूत करने और उभरते बाजारों में विस्तार करने के प्रयास कर रहे हैं, जिनकी पर्चेसिंग पावर बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य शादी के आभूषणों के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की पेशकश करके डायमंड ज्वेलरी की हिस्सेदारी को बढ़ाना है, जो वर्तमान में 6३ है। प्रीमियम मेकिंग चार्जेस की मांग करके, हम अपने ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाने का लक्ष्य रख रहे हैं।'

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने एस1 पोर्टफोलियो पर आकर्षक डील्स पेश कीं

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ओला इलेक्ट्रिक अपने ओला एस1 स्कूटरों की खरीद पर 25,000 रुपये तक के आकर्षक बेनेफिट्स प्रदान कर रहा है। 22 जुलाई तक लागू इन ऑफरों में एस1 एक्सऱ पर 10,000 रुपये और एस1 प्रो एवं एस1 एयर पर 5,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी चुनिंदा क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर ग्राहकों को 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रही है। इन ऑफर्स के अलावा ग्राहकों को ईएमपीएस 2024 के अंतर्गत 10,000 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। इन आकर्षक ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को कीमतें बढ़ने से पहले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदकर उसे रजिस्टर कराना होगा।

ओला इलेक्ट्रिक एक विशाल एस1 पोर्टफोलियो पेश करता है, जिसमें आकर्षक मूल्य में छः उत्पाद हैं, जो विभिन्न रेंज की जरूरत वाले ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। हाल ही में कंपनी ने मास-मार्केट सेगमेंट में अपना एस1 एक्स पोर्टफोलियो उतारा है। तीन बैटरी कन्फिगुरेशन (2 किलोवाट घंटा, 3 किलोवाट घंटा, और 4 किलोवाट घंटा) के साथ इन स्कूटरों का मूल्य क्रमशः 74,999 रुपये; 85,999 रुपये और 97,499 रुपये है। साथ ही इसके प्रीमियम स्कूटरों में एस1 प्रो, एस1 एयर, और एस1 एक्सऱ का मूल्य क्रमशः 1,28,999 रुपये, 1,01,499 रुपये और 84,999 रुपये है। ओला इलेक्ट्रिक अपने उत्पादों की संपूर्ण श्रृंखला पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के 8 सालॅ80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड बैटरी वॉरंटी प्रदान करता है। ओला इलेक्ट्रिक का मानना है कि इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की उम्र बढ़ेगी, और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में आने वाली एक बड़ी बाधा का समाधान हो सकेगा।

३० करोड़ में हेलीकॉप्टर बेचेगी AiRus! भारत में दूसरे प्लांट के लिए आठ शहर शॉर्टलिस्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

एयरक्राफ्ट बनाने वाली यूरोप की दिग्गज कंपनी एयरबस (AiRus) ने भारत में अपने दूसरे प्लांट यानी असेंबली लाइन को खोलने के लिए आठ साइटों को शॉर्टलिस्ट किया है। कंपनी ने भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (TASL) के साथ पार्टनरशिप की है। भारत में एयरबस की पहली असेंबली लाइन का उद्घाटन अगले कुछ दिनों में होना है जिसमें C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाए जाएंगे। भारत में कंपनी के दूसरे प्लांट में H125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। यह कंपनी का दुनिया में चौथा प्लांट होगा जिसमें सिंगल-इंजन हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। इससे पहले कंपनी फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका में इस तरह के प्लांट लगा चुकी है।इस प्लांट में हर साल 10 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा, जिनमें से पहला 2026 की शुरुआत में शुरुआत में तैयार होने की उम्मीद है। एयरबस को उम्मीद है कि पाकिस्तान को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप अगले 20 वर्षों में लगभग 500 ऐसे हेलीकॉप्टरों का बाजार होगा। इस हेलीकॉप्टर की कीमत 30 करोड़ रुपये से शुरू होती है। एयरबस हेलीकॉप्टर के एग्जीक्यूटिव वाइस-प्रेसिडेंट (ग्लोबल बिजनेस) Olivier Michalon ने बताया कि भारत में फाइनल असेंबली लाइन न केवल लीड टाइम, डिलीवरी टाइम के मामले में हमें प्रतिस्पर्धी बनाएगी, बल्कि यह हमें भारतीय बाजार के विकास और पड़ोसी देशों की मांग को पूरा करने में भी मदद करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मॉडल भारत में उतना ही सफल होगा जितना कि एयरबस ए 320 है। उन्होंने कहा कि एच 125 हमारा ए 320 है।

कहां बनी है पहली असेंबली लाइन

भारत में नई सुविधा फ्रांस के प्लांट की तर्ज पर होगी और इंजन सहित अधिकांश प्रमुख सबसिस्टम फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से आएंगे। एयरबस ने यह नहीं बताया कि सुविधा में कितना निवेश किया जाएगा या इसमें कितने लोग काम करेंगे। ब्राजील की फैसिलिटी लगभग 10 हेलीकॉप्टर बनाती है और लगभग 500 लोगों को रोजगार देती है। लेकिन इसके पास अतिरिक्त यूनिट्स भी हैं। भारत और दक्षिण एशिया में एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रमुख सनी गुगलानी ने बताया कि पिछले साल एयरबस ने भारत में दस प125 हेलीकॉप्टर बेचे थे।

वडोदरा में एयरबस की भारत में पहली असेंबली लाइन लगभग तैयार है जिसमें एयरफोर्स के लिए प295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। लेकिन Michalon ने यह बताने से इन्कार कर दिया कि गुजरात का यह शहर आठ साइटों में से एक है या नहीं। उन्होंने कहा कि साइट का फाइनल वैल्यूएशन चल रहा है। हम जल्द ही घोषणा करेंगे कि भारत में प125 कहां बनाए जाएंगे। एयरबस भारत और चीन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है क्योंकि इन देशों में आने वाले दशकों में एविएशन सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। कंपनी ने 2008 में चीन में अपनी पहली असेंबली लाइन खोली थी। वहां लोकप्रिय A320 यात्री जेट का उत्पादन किया जा रहा है जिसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपये है।

चीन वर्सेज इंडिया

पिछले साल एयरबस ने चीन में दूसरी असेंबली लाइन खोलने की घोषणा की थी। हालांकि चीन ने खुद A320 जैसा विमान कोमैक C919 विकसित किया है। सरकार खुद देसी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। पहले ही कोमैक C919 के लिए 1,000 ऑर्डर मिल चुके हैं। एयरबस के पास भारत की तुलना में चीन के ऑर्डर काफी कम हैं। चीनी एयरलाइनों ने कुल 357 एयरबस विमानों का ऑर्डर दिया है। वहीं भारतीय कंपनियों ने 1,216 एयरबस विमानों का ऑर्डर दिया है। इंडिगो ने 972 और एयर इंडिया ने 244 विमानों का ऑर्डर दिया है। भारत ने एयरबस और बोइंग से देश में असेंबली लाइन खोलने की मांग की है। एयरबस जहां दूसरी असेंबली लाइन खोलने की तैयारी में है, वहीं बोइंग ने अभी तक इस मामले पर निर्णय नहीं लिया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।